



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173 ]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2003/कार्तिक 14, 1925

No. 173]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2003/KARTIKA 14, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 31 अक्टूबर, 2003

सं. टीएएमपी/53/2003-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2003 के अपने पूर्ववर्ती आदेश द्वारा सभी महापत्तन न्यासों के लिए समान दरमान में दिनांक 28 अगस्त, 2003 के अपने पिछले आदेश द्वारा प्रस्तुत की गई, यह विनिर्दिष्ट करने वाली सामान्य सशर्तता में, कि उसमें निर्धारित दरें अधिकतम दरें हैं, संलग्न आदेशानुसार संशोधन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/53/2003-सामान्य

आदेश

(अक्टूबर, 2003 के 22वें दिन पारित)

भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन दिनांक 21 अगस्त, 2003 के पत्र सं. पीआर/11012/1/99-पीजी द्वारा इस प्राधिकरण को दरमान को अधिकतम दरों के रूप में निर्धारित करने और इसे अपने दरें निर्धारित करने संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित करने के लिए नीति निदेश जारी किया है ताकि महापत्तनों को अन्य पत्तनों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम दरों पर वसूली, यदि वे चाहें तो, करने का अधिकार हो। इसी प्रकार, इस प्राधिकरण द्वारा दरमान में निर्धारित छूट और कटौती निम्नतम स्तर के रूप में लागू होंगी और पत्तन न्यासों को उच्चतर छूट और कटौती करने का अधिकार होगा।

2.1. सरकार की नीति को लागू करने के लिए, इस प्राधिकरण ने निम्नलिखित सामान्य सशर्तता को शामिल करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों के दरमान में संशोधन करने हेतु दिनांक 28 अगस्त, 2003 को एक आदेश पारित किया था :

“दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम हैं; इसी प्रकार, कटौतियां और छूट निम्नतम हैं। पत्तन न्यास, यदि ऐसा चाहे तो, कम दरें वसूल कर सकता है और/अथवा उच्चतर कटौती और छूट दे सकता है।

2.2. यह आदेश 2 सितम्बर, 2003 को राजपत्र सं. 135 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

3. एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि जब पत्तन दरों में कमी करने का निर्णय लेते हैं तब पारदर्शिता सुनिश्चित कर लें। कम से कम, यह तो सुनिश्चित किया ही जाए कि जब पत्तन दरों में कमी करने का निर्णय लेते हैं तो सभी संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने दिनांक 3 अक्तूबर, 2003 के पत्र सं. पीआर-11012/1/99-पीजी द्वारा इस मत का समर्थन किया है।

4. इस प्राधिकरण को न केवल दरें निर्धारित करने के लिए बल्कि ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली सशर्तताएँ भी निर्धारित करने के लिए आदेशित है। दरमान में निर्धारित दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली सशर्तताओं में भी प्रशुल्क के निहितार्थ हैं। जबकि महापत्तन न्यासों को कम की गई दरें वसूल करने के लिए अधिकार दिया गया है तो ऐसे में सशर्तताओं को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा अधिकार नहीं देना असंगतता सिद्ध करता है। इसलिए, यह प्राधिकरण दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली सशर्तताओं को उदार बनाने/युक्तिसंगत बनाने के लिए, यदि ऐसा करने से उपयोगकर्ताओं को राहत मिलती है, महापत्तन न्यासों को अधिकार प्रदान करने को समुचित मानता है। परंतु, सशर्तताओं के ऐसे युक्तिकरण से इस प्राधिकरण द्वारा अधिकतम रूप में निर्धारित प्रति इकाई दर में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि 8 घंटों की इकाई के लिए दर निर्धारित है और पत्तन इकाई को कम करके में एक घंटे में बदलना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है बशर्ते प्रति घंटा अधिकतम दर को यथानुपात समायोजित किया गया हो। इस आधार पर कि वसूली की इकाई के युक्तिकरण से उपयोगकर्ताओं को समग्र रूप में लाभ होगा, इस प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना पत्तन यथानुपात दर से अधिक स्तर पर प्रति घंटा दर निर्धारित नहीं कर सकता।

5. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण अपने 28 अगस्त, 2003 को पारित आदेश द्वारा कार्यान्वित की गई सामान्य सशर्तता को निम्नलिखित सामान्य सशर्तता के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों के दरमान में संशोधन करता है :

*“दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम हैं; इसी प्रकार, कटौतियाँ और छूट निम्नतम हैं। पत्तन न्यास, यदि ऐसा चाहे तो, कम दरें वसूल कर सकता है और/अथवा उच्चतर कटौती और छूट दे सकता है।*

*पत्तन न्यास, यदि वह ऐसा चाहे तो दरमान में निर्धारित दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली निर्धारित सशर्तताओं को युक्तिसंगत बना सकता है। यदि ऐसे युक्तिकरण से उपयोगकर्ताओं को प्रति इकाई दर में राहत मिलती है, और दरमान में निर्धारित इकाई दरें अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होंगी।*

*इसके अलावा, पत्तन न्यास ऐसी निम्नतर दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली सशर्तताओं को युक्तिसंगत बनाए जाने की सार्वजनिक सूचना देनी होगी और ऐसी निम्नतर दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली सशर्तताओं में आगे किए जाने वाले किन्हीं बदलावों की सार्वजनिक सूचना देना जारी रखेगा बशर्ते नई निर्धारित दरें इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।”*

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/03/असाधारण]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 31st October, 2003

**No. TAMP/53/2003-Genl.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the general conditionality introduced in the Scale of Rates commonly for all the major port trusts vide its earlier Order dated 28th August, 2003 to specify that the rates prescribed therein are ceiling rates, as in the Order appended hereto.

**SCHEDULED**  
**No. TAMP/53/2003-Genl.**

**ORDER**

(Passed on this 22nd day of October 2003)

The Government of India in the Ministry of Shipping (MOS) vide its communication No. PR/11012/1/99-PG dated 21 August 2003 issued a policy direction to this Authority under Section 111 of the MPT Act to fix the Scale of Rates as ceiling rates and to so specify in its notification fixing rates so that the major ports have the flexibility to charge at reduced rates, if they so desire, to compete with others. Similarly, the discounts and rebates prescribed by this Authority in the Scale of Rates will act as the floor level and the port trusts will have the flexibility of giving higher discounts and rebates.

2.1. In order to implement the policy of the Government, this Authority passed an Order on 28 August 2003 to amend the Scale of Rates of all the major port trusts to insert the following general conditionality therein:

*The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The Port Trust may, if it so desires, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts".*

2.2. This Order was published in the Gazette of India on 2 September 2003 vide Gazette No.135.

3. One important issue which requires attention is ensuring transparency when ports take a decision to reduce rates. At least, it is to be ensured that when ports take a decision to reduce rates it must be made known to all concerned. The Ministry of Shipping (MOS) vide its communication No.PR-11012/1/99-PG dated 3 October 2003 has endorsed this view.

4. This Authority is mandated not only to fix the rates but also conditionalities governing the application of such rates. The conditionalities governing the application rates prescribed in the Scale of Rates also have tariff implications. While the major port trusts are given flexibility to charge reduced rates absence of such flexibility in application of conditionalities may prove incongruent. This Authority, therefore, considers it appropriate to provide the major port trusts with flexibility to relax / rationalise the conditionalities governing the application of rates if such rationalisation gives relief to the users. Such rationalisation of conditionalities, however, should not have the effect of increasing the rate per unit prescribed as ceiling by this Authority. For example, if a rate is prescribed for a unit of 8 hours in the Scale of Rates and the port wants to reduce the unit to one hour, it can do so provided the hourly ceiling rate is adjusted *pro rata*. On the ground that rationalisation of unit of levy will benefit users in totality, the port cannot fix hourly rate at a level higher than the *pro rata* rate without the approval of this Authority.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority amends the Scale of Rates of all the major port trusts to substitute the general conditionality introduced by the Order of this Authority passed on 28 August 2003 with the following general conditionality:

*"The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The Port Trust may, if it so desires, charge lower rates and or allow higher rebates and discounts.*

*The Port Trust may also, if it so desires, rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.*

*Provided that the Port Trust should notify the public such lower rates and / or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and / or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by this Authority".*

A.L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT /III/IV/143/03/Exty.]